



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3477]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 24, 2019/कार्तिक 2, 1941

No. 3477]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 24, 2019/KARTIKA 2, 1941

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2019

**का.आ. 3844(अ).—** यतः केन्द्र सरकार का दिल्ली मुख्य योजना -2021 के संबंध में जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17/07/2019 के का.आ. 2542(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से पैंतालिस दिन (45) के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा(3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में 1034 की संख्या में प्राप्त आपत्तियों/ सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित जांच और सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार कर लिया है और दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन भी प्रदान कर दिया है।

3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मुख्य योजना-2021 में जैसा कि आगे के पैरा में दिया गया है संशोधित करने का निर्णय लिया है।

4. अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है :

## संशोधन

क्र.सं.	विद्यमान प्रावधान	दि.मु.यो. 2021 प्रस्तावित संशोधन/परिवर्तन
1.	<p><b>पैरा 6.4.1.1</b></p> <p>v. अलग पड़े हुए गोदामों के स्वामियों को इस अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के अंदर नक्शों को अनुमोदित कराने की आवश्यकता होगी। असंगत क्षेत्रों में आने वाले प्लॉटों के स्वामियों और 30.0 मीटर से कम मार्ग पर अवस्थित मौजूदा गोदामों को इस एक वर्ष के अंदर अन्य संगत क्षेत्रों/गोदाम क्लस्टरों में स्थानांतरित होना होगा। असंगत क्षेत्रों में कार्यशील ऐसे गोदामों को उपर्युक्त समय अवधि के अंदर बंद करना होगा।</p>	<p><b>पैरा 6.4.1.1</b></p> <p>v. अलग पड़े हुए गोदामों के स्वामियों को <b>31.12.2020 तक</b> नक्शों को अनुमोदित कराने की आवश्यकता होगी। असंगत क्षेत्रों में आने वाले प्लॉटों के स्वामियों तथा 30.0 मीटर से कम मार्ग पर अवस्थित मौजूदा गोदामों को <b>31.12.2020 तक</b> अन्य संगत क्षेत्रों/गोदाम क्लस्टरों में स्थानांतरित होना होगा। असंगत क्षेत्रों में कार्यशील ऐसे गोदामों को उपर्युक्त समय अवधि के अंदर बंद करना होगा।</p>
2.	<p><b>15.7 अन्य कार्यकलाप</b></p> <p><b>15.7.1</b> पैरा 15.4 में दी गई सामान्य शर्तों और पैरा 15.7.3 में दी गई अतिरिक्त शर्तों के अधीन 15.7.2 में निर्दिष्ट न्यूनतम मार्गाधिकार की सड़कों के साथ, भले ही वे मिश्रित उपयोग सड़क के रूप में अधिसूचित हो या न हो, लगने वाले आवासीय प्लॉटों में भी निम्नलिखित सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक कार्यकलापों के लिए अनुमति दी जाएगी:</p> <p>.....</p> <p><b>टिप्पणी:</b> <b>कोई प्रावधान नहीं।</b></p>	<p><b>15.7 अन्य कार्यकलाप</b></p> <p><b>15.7.1</b> पैरा 15.4 में दी गई सामान्य शर्तों और पैरा 15.7.3 में दी गई अतिरिक्त शर्तों के अधीन 15.7.2 में निर्दिष्ट न्यूनतम मार्गाधिकार की सड़कों के साथ, भले ही वे मिश्रित उपयोग सड़क के रूप में अधिसूचित हो या न हो, लगने वाले आवासीय प्लॉटों में भी निम्नलिखित सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक कार्यकलापों के लिए अनुमति दी जाएगी:</p> <p>.....</p> <p><b>टिप्पणी:</b> <b>बैंक लॉकर यदि मौजूदा बैंक का भाग हो, तो उनके लिए उन्हीं परिसरों के संबंधित बेसमेंट में अनुमति दी जाएगी।</b></p>
3.	<p><b>15.7.5</b> <b>कोई प्रावधान नहीं।</b></p>	<p><b>15.7.5</b> वैध उपयुक्त लाइसेंस और सभी सांविधिक अनापत्तियों सहित अधिसूचना की तारीख को अथवा उससे पहले विद्यमान केवल भू-तल पर बने हुए रेस्टोरेंट्स केवल अधिसूचित मिश्रित उपयोग स्ट्रीट्स पर अनुमेय होंगे।</p>
4.	<p><b>15.9 मिश्रित उपयोग परिसरों का पंजीकरण और प्रभारों का भुगतान</b></p> <p>(ii) मिश्रित उपयोग परिसरों को केन्द्र सरकार के अनुमोदन के अधिसूचित दरों पर संबंधित स्थानीय निकाय को प्रत्येक वर्ष मिश्रित उपयोग प्रभारों का भुगतान करना होगा, जो उस अवधि के लिए होगा जितनी अवधि के लिए सम्पत्ति को मिश्रित उपयोग के लिए रखा जाता है। यह भुगतान सम्पत्ति के स्वामी/आबंटिती द्वारा स्वेच्छा से पिछले निर्धारण वर्ष (अप्रैल-मार्च) के लिए 30 जून से पहले किया जाएगा।</p> <p><b>वर्ष 2006-07 और 2007-08 हेतु मिश्रित उपयोग के लिए संपत्ति स्वामी/आबंटिती को दिनांक 30.06.2009 तक अथवा उससे पहले मिश्रित उपयोग हेतु खंड 15.9(v) के अंतर्गत किसी जुमाने का भुगतान किए बिना एक बारगी पंजीकरण प्रभार और वार्षिक परिवर्तन प्रभार का भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी।</b></p>	<p><b>15.9 मिश्रित उपयोग परिसरों का पंजीकरण और प्रभारों का भुगतान</b></p> <p>(ii) मिश्रित उपयोग परिसरों को केन्द्र सरकार के अनुमोदन के अधिसूचित दरों पर संबंधित स्थानीय निकाय को प्रत्येक वर्ष मिश्रित उपयोग प्रभारों का भुगतान करना होगा, जो उस अवधि के लिए होगा जितनी अवधि के लिए सम्पत्ति को मिश्रित उपयोग के लिए रखा जाता है। यह भुगतान सम्पत्ति के स्वामी/आबंटिती द्वारा स्वेच्छा से पिछले निर्धारण वर्ष (अप्रैल-मार्च) के लिए 30 जून से पहले किया जाएगा।</p>

[फा. सं. के-12011/5/2019-डीडी-1]

उपेन्द्र कुमार तिवारी, अवर सचिव

**MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS**

(DELHI DIVISION)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th October, 2019

**S.O. 3844 (E).**—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021, was published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice S.O. 2542(E) dated 17.07.2019 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within a stipulated time period of forty five (45) days.

2. Whereas, approx. 1034 numbers of objections / suggestions received with regard to the proposed modification have been considered by the Board of Enquiry and Hearing, set up by the Delhi Development Authority and also approved at the meeting of the Delhi Development Authority.

3. Whereas, the Central Government, after carefully considering all aspects of the matter, has decided to modify the Master Plan for Delhi-2021 as detailed in succeeding para.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

**Modifications:**

S. No.	MPD-2021	
	Existing Provision	Proposed Amendments/Modifications
1.	<p><b>Para 6.4.1.1</b></p> <p>v. Owners of standalone godowns needs to get the plans approved <b>within one year period from the date of this notification.</b> The owners of plots falling in non-conforming areas and existing godowns located on less than 30.0 m will have to shift to the other conforming areas / godown clusters within this one year. Such godowns functioning in non-conforming areas shall have to close down within the above said time period.</p>	<p><b>Para 6.4.1.1</b></p> <p>v. Owners of standalone godowns needs to get the plans approved <b>by 31.12.2020.</b> The owners of plots falling in non-conforming areas and existing godowns located on less than 30.0 m <b>ROW</b> will have to shift to the other conforming areas / godown clusters <b>by 31.12.2020.</b> Such godowns functioning in non-conforming areas shall have to close down within the above said time period.</p>
2.	<p><b>15.7 Other Activities</b></p> <p><b>15.7.1</b> Subject to the general conditions given in para 15.4 and additional conditions given in para 15.7.3, the following public and semi-public activities shall also be permitted in the residential plots abutting roads of minimum ROW prescribed in 15.7.2, whether or not the road is notified as mixed use street:</p> <p>.....</p> <p><b>Note:</b></p> <p><b>No Provisions</b></p>	<p><b>15.7 Other Activities</b></p> <p><b>15.7.1</b> Subject to the general conditions given in para 15.4 and additional conditions given in para 15.7.3, the following public and semi-public activities shall also be permitted in the residential plots abutting roads of minimum ROW prescribed in 15.7.2, whether or not the road is notified as mixed use street:</p> <p>.....</p> <p><b>Notes:</b></p> <p><b>Bank lockers if part of existing bank shall be allowed in the respective basements of same premises.</b></p>
3.	<p><b>15.7.5</b></p> <p><b>No Provisions</b></p>	<p><b>15.7.5 Restaurants on ground floor only with valid appropriate licenses and with all statutory clearances, as existing on or before the date of notification shall only be permissible on notified mixed use streets.</b></p>
4.	<p><b>15.9 Registration of Mixed Use Premises and Payment of Charges</b></p>	<p><b>15.9 Registration of Mixed Use Premises and Payment of Charges</b></p>

<p>(ii) The premises under mixed use shall also be liable for payment of mixed- use charges every Year to the local body concerned at the rates notified with the approval of Central Government, for the period during which the property is put to mixed use. Such payment will be made by the property owner/allottee voluntarily before 30th June of every year in respect of the previous assessment year (April - March).</p> <p><b>For mixed use for the year 2006-07 and 2007-08, the property owner/ allottee shall be allowed to pay one time registration charges and annual conversion charges without payment of any penalty under Clause 15.9 (v) for mixed use on or before 30.6.2009.</b></p>	<p>(ii) The premises under mixed use shall also be liable for payment of mixed- use charges every Year to the local body concerned at the rates notified with the approval of Central Government, for the period during which the property is put to mixed use. Such payment will be made by the property owner/allottee voluntarily before 30th June of every year in respect of the previous assessment year (April - March).</p>
---	---

[ F.No. K-12011/5/2019-DD-I]

UPENDRA KUMAR TIWARI, Under Secy.